

## चुनाव में 'मुफ्त' का आकर्षण

यह एडिटरियल 29/04/2022 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Are Freebies Affecting the Economic Growth of India?" लेख पर आधारित है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त मुफ्त उपहारों या 'फ्रीबीज़' (freebies) के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के पतन की हालिया खबरों ने राज्य की भूमिका पर एक नई बहस को जन्म दिया है। श्रीलंका की सरकार ने सभी के लिये करों में कटौती और वभिन्न मुफ्त वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण जैसे कदम उठाए थे। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ से उसके पतन की स्थिति बनी और पहले से ही भारी कर्ज में डूबे देश के पास अपनी प्रतबिद्धताओं पर डिफॉल्ट दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

- इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राज्यों द्वारा दिए जा रहे **मुफ्त उपहारों या 'फ्रीबीज़' (freebies)** के मुद्दे पर भारत में भी एक बहस की शुरुआत हुई है। समय के साथ फ्रीबीज़ भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गए हैं, चाहे वे चुनावी संघर्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिये वादे के रूप में हों या उनका उद्देश्य सत्ता में बने रहने के लिये मुफ्त सुविधाएँ प्रदान करना हो।

### फ्रीबीज़ क्या हैं?

- राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिये मुफ्त बजिली/पानी की आपूर्ति, बेरोज़गारों, दहिाड़ी मज़दूरों एवं महिलाओं के लिये मासिक भत्ते के साथ-साथ लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स देने का वादा करते हैं।
  - राज्यों को फ्रीबीज़ प्रदान करने की आदत ही हो गई है, चाहे वह ऋण माफी के रूप में हो या मुफ्त बजिली, साइकलि, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में।
- लोकलुभावन दबावों या चुनावों को ध्यान में रखकर किये जाने वाले ऐसे कुछ खर्चों पर नश्चय ही प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
  - लेकिन यह देखते हुए कि पिछले 30 वर्षों से देश में असमानता बढ़ रही है, सब्सिडी के रूप में आम आबादी को किसी प्रकार की राहत प्रदान करना अनुचित नहीं माना जा सकता, बल्कि वास्तव में अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर बने रहने के लिये यह आवश्यक है।

### फ्रीबीज़ के पक्ष में तर्क

- **विकास को सुगम बनाना:** ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएँ, शिक्षा के लिये सहायता और स्वास्थ्य जैसे वषियों में किये जाने वाले परवियय वास्तव में समग्र लाभ का सृजन करते हैं। महामारी के दौरान वशेष रूप से इसकी पुष्टि भी हुई।
  - ये जनसंख्या की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में दीर्घकालिक योगदान करते हैं और एक स्वस्थ एवं सशक्त कार्यबल के निर्माण में मदद करते हैं, जो किसी भी विकास रणनीति का एक आवश्यक अंग है।
  - शिक्षा या स्वास्थ्य पर राज्य द्वारा किये जाने वाला व्यय भी यही योगदान देता है।
- **उद्योगों को बढ़ावा:** तमलिनाडु और बिहार जैसे राज्य महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ी और साइकलि जैसे लाभ दे रहे हैं, लेकिन वे इन वस्तुओं की खरीद अपने बजट राजस्व से करते हैं जिससे संबंधित उद्योगों की बिक्री बढ़ाने में भी योगदान करते हैं।
  - संबंधित उत्पादन वृद्धि को देखते हुए इसे आपूर्तिकर्ता उद्योग के लिये प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है, न कि फिज़िलखर्ची के रूप में।
- **अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये आवश्यक:** भारत जैसे देश में जहाँ राज्यों में विकास का एक नश्चित स्तर पाया जाता है (या नहीं पाया जाता है), चुनावों के समय लोगों की ओर से ऐसी अपेक्षाएँ प्रकट की जाती हैं, जिन्हें फ्रीबीज़ के ऐसे वादों से पूरा किया जाता है।
  - इसके अलावा, जब पड़ोस के या देश के अन्य राज्यों (अलग-अलग दलों द्वारा शासित) के लोगों को फ्रीबीज़ प्राप्त हो रहे होते हैं तो इधर भी तुलनात्मक अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं।
- **कम विकसित राज्यों की सहायता:** गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से विकास के निम्न स्तर पर स्थित राज्यों के लिये इस तरह के फ्रीबीज़ आवश्यकता या मांग-आधारित बन जाते हैं और अपने स्वयं के उत्थान हेतु लोगों के लिये इस तरह की सब्सिडी की पेशकश करना आवश्यक हो जाता है।

## फ्रीबीज़ के वपिक्ष में तरक

- **मैक्रोइकोनॉमिक रूप से असंवहनीय:** फ्रीबीज़ मैक्रोइकोनॉमिक संवहनीयता/स्थरिता के बुनयादी ढाँचे को कमज़ोर करते हैं। फ्रीबीज़ की राजनीति वयय प्राथमकताओं को वकृत करती है और परवियय के कसिी न कसिी तरह की सब्सडी पर केंद्रति बने रहने की प्रवृत्ता उभरती है।
- **राज्यों की वततीय स्थति पर प्रभाव:** फ्रीबीज़ देने का अंततः राजकोष पर प्रभाव पड़ता है, जबक भारत के अधिकांश राज्य एक सुदृढ़ वततीय स्थति नहीं रखते और उनके पास राजस्व के मामले में प्रायः अत्यंत सीमति संसाधन ही होते हैं।
  - यद राज्ज कथति राजनीतिक लाभ के लयि वयय करना जारी रखेंगे तो उनकी वततीय स्थति लिड़खड़ा जाएगी और राजकोषीय अपवययति की स्थति बिनेगी।
    - राजकोषीय उत्तरदायतिव और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) नयिमें के अनुसार राज्ज अपनी कषमता या सीमा से अधिक उधार नहीं ले सकते और उनके कसिी भी वचिलन (या अलग मद के खर्च) को केंद्र और केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदति कयिा जाना आवश्यक है।
    - इस प्रकार, भले ही राज्यों के पास यह लचीलापन है क वी अपना पैसा कैसे खर्च करना चुनते हैं, वे सामान्य परस्थितियों में अपनी घाटे की सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं।
- **स्वतंत्र एवं नषिपकष चुनाव की भावना के वरिद्ध:** चुनाव से पहले लोकलुभावन फ्रीबीज़ (सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए) का वादा मतदाताओं को अनुचति रूप से प्रभावति करता है, सभी दलों के लयि समान अवसर की स्थति में व्यवधान लाता है और चुनाव प्रक्रया की शुद्धता को मलनि करता है।
  - यह एक अनैतिक अभ्यास है जो मतदाताओं को रशिवत देने के समान है।
- **पर्यावरण से एक कदम दूर:** जब ये फ्रीबीज़ मुफ्त बजिली अथवा एक नशिचति मात्रा में मुफ्त बजिली, पानी और अन्य प्रकार की उपभोग वस्तुओं के रूप में प्रदान कयिा जाते हैं, तो ये पर्यावरण एवं सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और अधिक कुशल सार्वजनिक परविहन प्रणालयिों के मद में कयिा जा सकने वाले परवियय को वचिलति करते हैं।
  - इसके अलावा, यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ता है क जब कोई चीज़ 'मुफ्त' में प्रदान की जाती है तो इनका अत्यधिक उपयोग कयिा जाता है, इस प्रकार संसाधनों की बर्बादी होती है।
- **भवषिय के वनिरिमाण पर दुर्बलकारी प्रभाव:** फ्रीबीज़ वनिरिमाण कषेत्र में उच्च-गुणक दक्षता को सक्षम करने वाले कुशल एवं प्रतसिप्रर्द्धी अवसंरचना को बाधति कर वनिरिमाण कषेत्र की गुणवत्ता एवं प्रतसिप्रर्द्धात्मकता को कम कर देते हैं।
- **'करेडिट कल्चर' का वनिाश:** फ्रीबीज़ के रूप में ऋण माफी (Loan Waivers) के अवांछति परणाम भी सामने आ सकते हैं; जैसे कयिह संपूर्ण करेडिट कल्चर को नषट कर सकता है और यह इस बुनयादी प्रश्न को धुंधला कर देता है क ऐसा क्यों है क किसान समुदाय का एक बड़ा भाग बार-बार कर्र के जाल में फँसता रहता है।

## आगे की राह

- **फ्रीबीज़ के आर्थिक प्रभावों को समझना:** सवाल यह नहीं क फ्रीबीज़ कतिने ससूते हैं, बल्क यह है क दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लयि वे कतिने मंहंगे साबति हो सकते हैं।
  - इसके बजाय हमें लोकतंत्र और सशक्त संघवाद की प्रयोगशालाओं के माध्यम से दक्षता की दौड़ के लयि प्रयास करना चाहयि जहाँ राज्ज अपने प्राधिकार का उपयोग नवीन वचिरों एवं सामान्य समस्याओं के समाधान के लयि करें, जनिा फरि अन्य राज्ज भी अनुकरण कर सकते हैं।
- **वविकपूर्ण मांग-आधारति फ्रीबीज़:** भारत एक बड़ा देश है और यहाँ अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह मौजूद है जो गरीबी रेखा से नीचे है। देश की विकास योजना में सभी लोगों को शामिल कयिा जाना भी ज़रूरी है।
  - ऐसे फ्रीबीज़ या सब्सडी की उचति एवं वविकपूर्ण पेशकश, जसिे राज्यों के बजट में आसानी से समायोजति कयिा जा सकता है, अधिक नुकसानदायक नहीं होगा और इनका लाभ उठाया जा सकता है।
  - संसाधनों के बेहतर समग्र उपयोग को सुनिश्चति करने के लयि राज्ज वयय का एक अनुपात नरिधारति कयिा जाना चाहयि।
- **सब्सडी और फ्रीबीज़ में अंतर करना:** फ्रीबीज़ के प्रभावों को आर्थिक नज़रयि और करदाताओं के धन से जोड़कर देखने की ज़रूरत है।
  - सब्सडी और फ्रीबीज़ में अंतर करना भी आवश्यक है कयोंक सब्सडी उचति और वशिष रूप से लक्षति लाभ हैं जो मांगों से उत्पन्न होते हैं।
  - यदयपि प्रत्येक राजनीतिक दल को लक्षति ज़रूरतमंद लोगों को लाभ देने के लयि सब्सडी पारतित्र के नरिमाण का अधिकार है, राज्ज या केंद्र सरकार के आर्थिक स्वास्थय पर दीर्घकालिक बोझ नहीं होना चाहयि।

**अभ्यास प्रश्न:** "समय के साथ फ्रीबीज़ भारतीय राजनीति का अभनिन अंग बन गए हैं। यदयपि सार्वजनिक वतिरण योजना और मनरेगा जैसी कुछ पहलें भारत की विकास रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गई हैं, फ्रीबीज़ मैक्रोइकोनॉमिक स्थरिता के बुनयादी ढाँचे को कमज़ोर भी करते हैं।" चर्चा कीजयि।